मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा– किसी भी वैश्विक नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा।
- गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया – सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया।
- कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी।
- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य के प्रमुख मंदिरों में भीड़ प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों से सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए।
- शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा– राज्य सरकार, युवाओं को सशक्त बनाने के लिये, विद्यालयों में कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

लोकसभा/आपरेशन सिंदूर पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के किसी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा है। लोकसभा में कल देर शाम ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने अमरीका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्धविराम समझौते पर सहमति देने के विपक्ष के आरोप को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ही भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने का आग्रह किया था और कहा था कि वे अब और नहीं सह सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र 22 मिनट में आतंकी हमले का बदला ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीन सूत्र तय किये हैं। इससे पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान सोमवार एक संयुक्त अभियान में पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया।

बाघ संरक्षण/अग्निवीर तैनाती

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कल यह घोषणा की। इस फोर्स में 80 से अधिक युवाओं की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का मुख्य उद्देश्य बाघों और उनके आवास की सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध शिकार पर रोक लगाना और वन्यजीव अपराधों पर नियंत्रण करना होगा। प्रशिक्षित जवान, वन क्षेत्रों में गश्त करेंगे, खुफिया जानकारी जुटाएंगे और शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह फोर्स लकड़ी की तस्करी, अवैध खनन और अतिक्रमण जैसे अपराधों पर भी नियंत्रण रखेगी। उन्होंने कहा कि यह बल, मानव–वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में भी मदद करेगा। कई बार बाघ आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, ऐसे मामलों में प्रशिक्षित जवान स्थिति को नियंत्रित करेंगे ताकि किसी पक्ष को नुकसान न हो। फोर्स को ड्रोन, थर्मल इमेजिंग और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर सेना के कठोर अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजर चुके हैं, जिससे वे वन गश्त और अपराध नियंत्रण में प्रभावी साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने इसे बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व को एक समर्पित और प्रशिक्षित बल की सुरक्षा मिलने से अवैध शिकार में कमी आएगी।

सर्वेक्षण निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य के प्रमुख मंदिरों में भीड़ प्रबंधन के लिए पहले चरण में मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ, कैंचीधाम और पूर्णागिरि मंदिर का विशेषज्ञों से सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को विशेषज्ञ टीम को सभी आवश्यक सहयोग देने को कहा। सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों को प्राथमिकता पर चिन्हित किया जाए जहां विशेष अवसरों पर अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति की आशंका रहती है। इन स्थलों पर अंशकालिक और दीर्घकालिक भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने मंदिर मार्गों से अतिक्रमण हटाने, मार्ग चौड़ीकरण और तकनीक के उपयोग से भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अत्यधिक भीड़ की स्थिति में श्रद्धालुओं को रोकने के लिए पूर्वनिर्धारित स्थान बनाए जाएंगे। विशेषज्ञ टीम मंदिर क्षेत्र का विश्लेषण कर भीड़ प्रबंधन, निकासी योजना और मार्ग सुधार के लिए विस्तृत योजना और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी। प्रत्येक मंदिर के लिए मार्ग और संचलन योजना बनाई जाएगी, ताकि अचानक भीड़ से होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

कौशल आधारित शिक्षा

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि युवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभा सकें। नई दिल्ली में ''अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025'' में भाग लेने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए प्री–प्राइमरी स्तर पर लगभग 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 'बालवाटिका' कक्षाएं शुरू कीं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट क्लासेज और आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

उन्होंने बताय कि राज्य में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा लागू की गई है, जिसमें कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और अन्य कौशल आधारित पाठ्यक्रम शामिल हैं। उच्च शिक्षा में औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एमओयू कर नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, ताकि शैक्षणिक वातावरण को और बेहतर बनाया जा सके।

नई व्यवस्था/पेंशन सरलीकरण

राज्य में दिव्यांग पेंशन योजना को वृद्धावस्था पेंशन योजना की तरह सरलीकृत करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब ऐसे दिव्यांगजन भी पेंशन के पात्र होंगे जिनके पुत्र या पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं। पहले इस स्थिति में पात्रता समाप्त हो जाती थी, लेकिन अब इस प्रावधान को हटाकर दिव्यांगजनों को राहत दी गई है। सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने निर्देश दिए हैं कि चार हजार रुपये मासिक आय सीमा के भीतर आने वाले सभी दिव्यांगजन, जिनके पुत्र या पौत्र वयस्क हैं, पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र रहेंगे। बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जिससे राज्य के हजारों दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

लोकार्पण

नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में संचालित केंद्रीय विद्यालय को अपना नया भवन मिल गया है। लगभग 25 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से और मौके पर उपस्थित सांसद अजय भट्ट ने किया।

कार्रवाई

देहरादून के कुठालगेट क्षेत्र में निर्माणाधीन साइट पर अवैध खनन की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी मसूरी के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी, पोकलैंड मशीन और खनन परिवहन में लगी दो पिकअप जब्त कर सील कर दीं। मौके पर सात लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया और संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। गौरतलब है कि जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की है। प्रशासन ने कहा है कि अवैध खनन पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में भीड़ प्रबंधन पर होगा सर्वे– यह खबर सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। अमर उजाला लिखता है – सुरक्षा और भीड़ के लिए मंडलायुक्त होंगे नोडल अधिकारी। इसी पर दैनिक जागरण का शीर्षक है – धर्म स्थलों में भीड़ प्रबंधन को सर्वेक्षण करेंगे विशेषज्ञ।

कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित की जा रही टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में उत्तराखंड के अग्निवीरों को सीधी तैनाती की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है– अग्निवीरों की टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में होगी सीधी भर्ती।